इस्पात का उत्पादन

775. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में विभिन्न प्रकार के इस्पात के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और वर्तमान में देश में स्टेनलैस स्टील की मांग की तुलना में इसका उत्पादन कितना है ;

(ख) इस्पात के उत्पादन में उपलब्ध उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भारत में उत्पादित इस्पात की तुलना में विदेशों में उत्पादित इस्पात के सस्ते और अच्छी क्वालिटी के होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) देश में तैयार इस्पात के उत्पादन में वर्ष 1983-84 के मुकाबले में वर्ष 1984-85 में 3 प्रतिशत, वर्ष 1984-85 के मुकाबले में वर्ष 1985-86 में 18 प्रतिशत और वर्ष 1985-86 के मुकाबले में वर्ष 1986-87 में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्टेनलैस स्टील के उत्पादन और मांग के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में क्षमता के उपयोग में कमी के लिए उत्तरदायी कारणों में ये कारण सम्मिलित हैं—कच्चे माल की घटिया क्वालिटी, पुरानी प्रौद्योगिकी, पुराने उपस्कर, बिजली की सप्लाई में कमी और प्रबंधक-कर्मचारी संबंधों की समस्याएं। "सेल" के कारखानों में कार्य-संस्कृति और सामान्य उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रयास किये गये हैं।

(ग) अन्य देशों में उत्पादित इस्पात के देशीय मूल्य भारत में उत्पादकों के मूल्यों के तुलनीय हैं। भारतीय इस्पात के मूल्यों की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्याप्त अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा में, निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीति के रूप में प्रायः कम कर दिया जाता है। भारत में एकीकृत इस्पात कारखानों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले इस्पात की क्वालिटी भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित ग्रेडों के अनुरूप है।

राजभाषा के कार्यान्वयन में लापरवाही

776. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा कितने प्रतिशत कार्य राजभाषा में किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा की उपेक्षा करते हैं और अन्य विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में जानबूझ कर विलम्ब करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह मंत्रालय सभी विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों में संसद के आधा दर्जन सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये जिम्मेदार है ; और

(घ) क्या इस मंत्रालय ने 61 हिन्दी सलाहकार समितियों में से 29 में संसद सदस्यों को नाम-निर्देशित नहीं किया है और इस कारण अभी तक उनका गठन नहीं हो पाया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पहली बार गठन 18-5-1984 को हुआ।

समिति की अभी तक सात बैठकें हो चुकी हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा राजभाषा में किए गए कार्य के प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा की उपेक्षा नहीं करते हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाह कार समिति के गठन में जानबूझ कर विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इनका गठन संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से निवेदन प्राप्त होने पर यह मंत्रालय 2 लोक सभा सदस्य और 2 राज्य सभा सदस्य को संबंधित मंत्रालय/विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति पर नामित करता है।

(घ) आठवीं लोक सभा के गठन से इस मंत्रालय में 39 मंत्रालयों/विभागों से उनकी सलाहकार समिति पर संसद सदस्यों के नामांकन के लिए निवेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय मंत्रालय में किसी भी मंत्रालय/विभाग का हिन्दी सलाहकार समिति पर संसद सदस्यों के नामांकन के लिए कोई निवेदन लम्बित

Conversion of Agriculture Land for Construction of Flats

777. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some cooperative group housing socieites got agriculture land converted for construction of Cooperative Group Housing Flats; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) Some Cooperative Group Housing Societies have been allotted land by the DDA in the area shown as "Agricultural green belt" in Master Plan for Delhi 1962. The case for change of land use is under process as a part of the finalisation of the Perspective Development Plan for Delhi-2001.

Post-Harvest Handling Facilities for Foodgrains

778. SHRI RAM AWADHESH SINGH:
SHRI VIRENDRA VERMA:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what has been the percentage with value of the foodgrains output lost annually due to lack of post-harvest handling facilities during the last three years and the current year, till date; and

(b) what efforts have been made by Government in the field of research and development of infrastructure and technology for handling the farm produce keeping in pace with the increase in production and thereafter transferring it to the fields stating the results achieved so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) No systematic comprehensive studies to asses the foodgrains lost annually due to lack of the post-harvest handling facilities have been made. However, the Expert Committee of Government of India on post-harvest losses in 1966 had estimated that about 9 per cent was lost during post-harvest operations and storage.

(b) The Research, Development and Training for improving the storage conditions of foodgrains are being undertaken at the Indian Grain Storage Institute, Hapur with its five field stations in the country. In addition, 17 regional Central Save Grain teams have been set up to give a lead to the States and play a catalytic role in the dissemination of improved storage practices for better preservation of foodgrains at the farm level. The major planks of the campaign are: Training, Demonstration and Publicity in selec-